सदियों से क्रोएशिया, बॉस्निया और हर्ज़गोविना की औरतें अपनी बेटियों के शरीर पर गोदना गोदती रही हैं। इस प्राचीन परंपरा को "सिकान्ये" कहते हैं। इस शब्द का अर्थ है, सुई चुभाना। शहद, कालिख, थूक और दूध (ब्रैस्टमिल्क) के मिश्रण में सुई डुबोकर हाथ, छाती और कभी-कभी माथे पर डिज़ाइन बनाए जाते थे। 1920 के दशक में मानवविज्ञानी ईडिथ डरहम ने लिखा था कि, 4000 सालों तक "सिकान्ये" की परम्परा महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहीं। लेकिन 20 वीं सदी के मध्य में यह परम्परा लुप्त हो गई। तथापि, अब बाल्कन महिलाओं व पुरुषों की नई पीढ़ी अपनी विरासत को पुनः पहचान देने के लिए इस परम्परा को पुनर्जीवित कर रही है। यह तो पता नहीं है कि, कांस्य युग के इन आदिवासियों में टैटू बनाने की परम्परा कब और क्यों शुरु हुई, पर शायद इसका सम्बंध धर्म या सामाजिक स्तर से रहा होगा। सिकान्ये प्रोजैक्ट की सहलेखक मारिया मरैसिक कहती हैं, "दुर्भाग्यवश हमारे पास इस परम्परा की उत्पत्ति के प्राथमिक स्रोत नहीं हैं।" बॉस्निया में जन्मी मारिया मरैसिक ने अमेरिका की क्लीवलैंड स्टेट युनिवर्सिटी में आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि, प्राचीन यूनानियों ने अपने लिखित इतिहास, गुलदस्तों व अन्य कलाकृतियों पर बाल्कन लोगों को टैटू के साथ चित्रित किया था। पुराविदों को 3000 साल पुराने मकबरों से तांबे की सुइयाँ मिली हैं जो टैटू बनाने के काम आती थीं। कुछ प्राचीन डिज़ाइन तो बहुत आम थे, जैसे कोलो सर्किल, जो परिवार की एकता का प्रतीक था। इसी नाम का एक पारम्परिक नृत्य आज भी इन क्षेत्रों की शादियों व अन्य समारोहों में किया जाता है। गांव व जाति के प्रतीक के रुप में भी टैटू बनते थे। असल में सिकान्ये का सम्बंध पहचान के साथ साथ, सुरक्षा, आशीर्वाद व सौंदर्य से भी रहा है। पंद्रहवी सदी में इसमें परिवर्तन आया। महिलाएं अपने बेटों के शरीर पर टैटू बनाने लगीं। ऑटोमन के राज में ईसाई बाल्कन परिवारों से टैक्स वसूला जाता था, जिसके तहत आठ साल के लड़कों को इस्ताम्बूल ले जाया जाता था जहां वे राजा के आसपास रहते थे। हालांकि बड़े होकर ये बच्चे उच्च पदस्थ सैनिक व अधिकारी बनते थे, लेकिन घर से फिर भी बहुत दूर थे। इसलिए माताएं अपने लड़कों के शरीर पर भी टैटू बनाने लगीं, क्योंकि, बच्चे जब लौटते थे तो परिवार उन्हें पहचान लेता था। बीसवीं सदी में सोशलिस्ट फैडरल रिपब्लिक युगोस्लाविया के काल में यह परम्परा खत्म होने लगी, महिलाओं ने अपने टैटू छिपाना शुरु कर दिया और लड़कियों ने टैटू बनवाने से मना कर दिया।

हाड़ौती कांग्रेस में अंतर्द्वंद, भाया समर्थक विधायकों ने भरत सिंह को बताया जयचंद

विधायक मेघवाल और सहरिया ने कहा, "हाड़ौती में पार्टी को कमजोर करने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं भरत सिंह"

- **इससे पहले शांति धारीवाल और नईमुद्दीन गुड्डू के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर हो ही चुकी है।**
- **भाया समर्थक विधायकों ने कहा, "जमीन से जुड़े कांग्रेसी ऐसी ओछी हरकतों से डरते नहीं हैं।"**

जयपुर, 22 जनवरी (का.प्र.)। अब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्सेस पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेल के बीच अंतर्द्वंद चल रहा था। वहीं हाड़ौती में पहले ही कोटा में मंत्री शांति धारीवाल और लाडपुरा के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के बीच सीधा टकराव चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक भरत सिंह लगातार मंत्री प्रमोद जैन भाया पर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे, तो अब प्रमोद जैन भाया समर्थक दो विधायकों ने जवाबी हमला करते हुए भरत सिंह पर आरोप लगा दिया है कि, वे हाड़ौती में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

भाया समर्थक दो विधायक पानाचंद मेघवाल और निर्मला सहरिया ने भरत सिंह को कांग्रेस का जयचंद बताते हुए कहा है कि, भरत सिंह हाड़ौती में पार्टी को कमजोर करने के लिए ओछी हरकतें कर रहे हैं। आए दिन अनावश्यक रूप से बारां में विरोध प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले प्रमोद जैन भाया समर्थक 2 विधायकों के खुलकर भरत सिंह के खिलाफ सामने आने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई और खुलकर सामने आती दिख रही है। पिछले 1 सप्ताह से जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रदेश के दौरे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयानों से सियासी पारा गर्म था। अब खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया और सांगोद विधायक भरत सिंह की अदावत तेज होती दिख रही है। भरत सिंह खान की झोपड़िया गांव को कोटा जिले में शामिल करवाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि, वो आगामी 23 जनवरी को विधानसभा करेंगे।

भरत सिंह के इस बयान और बारां में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन पर पर पलटवार करते हुए भाया के समर्थक बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल और किशनगंज शाहबाद विधायक निर्मला सहरिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि, हाड़ौती में पार्टी को कमजोर करने के लिए वो ओछी हरकतें कर रहे हैं। बिना वजह बारां में विरोध प्रदर्शन कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रहे है।

इससे पहले सांगोद विधायक भरत सिंह कई बार मंत्री भाया को भ्रष्ट और मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत पर दबाव बनाते रहे हैं। इसी के साथ लंबे समय से अवैध खनन, गोडावण, खान की झोपड़िया और सोरसन के मुद्दे को उठाते रहे हैं।

अब बारां अटरू के विधायक मेघवाल और निर्मला सहरिया ने संयुक्त बयान दिया है कि, हम विधायक भरत सिंह का सम्मान करते हैं। वे वरिष्ठ व पार्टी के पुराने नेता हैं। उन्हें और उनके परिवार को कांग्रेस से बहुत कुछ मिला है, लेकिन जब से बारां और कोटा अलग जिले से बने हैं, तभी से भरत सिंह बारां के कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे हैं। जिससे नेता के साथ ही पार्टी की छवि भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे उनकी कुंठा दिन-ब-दिन जाहिर हो रही है। साथ ही कहा है कि, भरत सिंह कई बार मुख्यमंत्री को लेकर भी भला बुरा कह चुके हैं। ऐसा ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के साथ किया है।

दोनों विधायकों ने कहा है कि, भरत सिंह की यह हरकतें हाड़ौती और विशेष रूप से बारां जिले में कांग्रेस को कमजोर करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। बारां कांग्रेस के गढ़ खान की झोपड़िया गांव को कोटा जिले में मिलाने की कोई कोशिश भरत सिंह ने तब क्यों नहीं की, जब वे राज्य सरकार में मंत्री थे। अब यह निर्णय बारां जिले के स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है। इसके बावजूद यहां धरना प्रदर्शन कर माहौल खराब करने की ओछी हरकत कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। विधायक मेघवाल और सहरिया ने आरोप लगाया कि, बारां के विकास को रोकने के लिए इन्होंने सबसे पहले गोडावन मुद्दे को उठाया और अब खान की झोपड़िया के मुद्दे को उठा रहे हैं। यह आगे भी ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे। हम बारां की जमीन से जुड़े कांग्रेसी ऐसी ओछी हरकतों से डरते नहीं हैं। ऐसे में अब हम भरत सिंह की इस ओछी हरकत और मानसिकता की निंदा करते हैं। भरत सिंह का यह कृत्य जयचंद जैसा व्यवहार करने की तरह है, लेकिन हम बारां के कांग्रेसी राहुल गांधी के नेतृत्व में देश-प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने और भारत को जोड़ने की मुहिम में लगे रहेंगे।

'पांच फीसदी लोगों का देश की 60 फीसदी संपत्ति पर कब्जा हो गया है'

कांग्रेस ने कहा कि, देश के प्रति व्यक्ति कर्ज में ढ़ाई गुना का इजाफा हुआ है

- **कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लव ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि, जिन लोगों के पास 60 फ़ीसदी संपत्ति है उनका देश के जीएसटी में योगदान महज तीन प्रतिशत है और जिन लोगों के पास देश की महज तीन फीसदी संपत्ति है उनका जीएसटी में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है।**

नई दिल्ली 22 जनवरी (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां अरबपतियों की आय बढ़ाने और जनसामान्य की आय घटाने का काम कर रही है जिससे देश में आर्थिक असमानता की खाई और चौड़ी हो रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लव ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रति व्यक्ति आय घट रही है और महज 5 फ़ीसदी लोगों का देश की 60 फ़ीसदी संपत्ति पर कब्जा हो गया है और प्रति व्यक्ति कर्ज ढाई गुना कार इजाफा हुआ है।

उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों के पास 60 फ़ीसदी संपत्ति है उनका देश के जी.एस.टी. में योगदान महज तीन प्रतिशत है और जिन लोगों के पास देश की महज तीन फीसदी संपत्ति है उनका जी.एस.टी. में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है।

प्रवक्ता ने कहा कि 2014 में मोदी साहब ने जब सत्ता संभाली तो देश में कर्ज 55 लाख करोड़ था जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

सवाल है पिछले नौ साल में कर्ज ढाई गुणा कैसे बढ़ा है। उनका कहना था कि देश के हर नागरिक पर एक लाख से ज्यादा कर्ज हो गया हैं लेकिन उसका फायदा सबको नहीं बल्कि देश के 5 प्रतिशत अमीरों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में सबका आखिर विकास होना चाहिए था लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कुछ ही अरबपतियों को फायदा हो रहा है और उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ रही है जबकि संपत्ति उन लोगों की बढ़ने चाहिए थी जो जी.डी.पी. में योगदान दे रहे हैं लेकिन उन लोगों पर कर्ज बढ़ रहा है।

राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ संयम लोढ़ा का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

- **विधायकों के त्याग पत्र का मामला विचाराधीन था और विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं दिया, उससे पहले ही जनहित याचिका हाइकोर्ट में पेश करने से विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना की गई, विधानसभा के विशेष अधिकारों का भी हनन किया गया।**
- **राठौड़ ने किया पलटवार, "मुख्यमंत्री के घोषित सलाहकार को बधाई, उन्हें 91 विधायकों के इस्तीफों के कोर्ट में डेढ़ महीने से विचाराधीन मामले का अब ध्यान तो आया।**

जयपुर, 22 जनवरी (का.प्र.)। भाजपा विधायक दल के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में 91 विधायकों के इस्तीफे को लेकर जनहित याचिका दायर करने के मामले में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 157 के अंतर्गत राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। लोढ़ा ने 23 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान 24 जनवरी को सदन में इस मामले को उठाने की अनुमति मांगते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (ख) के प्रावधान का जिक्र किया है, जो कि इस्तीफा लेटर से संबंधित है। इसी तरह प्रस्ताव में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 173 (2) का भी प्रस्ताव में जिक्र किया है, जो कि सदस्यों के त्याग पत्र से संबंधित है।

लोढ़ा ने अपने प्रस्ताव में कहा कि सदस्यों के त्याग पत्र का मामला विचाराधीन था और विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में अपना कोई फैसला नहीं दिया था। उससे पहले ही 1 दिसंबर 2022 को जनहित याचिका हाइकोर्ट में पेश करने से न केवल विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना की गई है, बल्कि राजस्थान विधानसभा के विशेष अधिकारों का भी हनन किया गया है।

लोढ़ा ने इस प्रस्ताव के जरिए 24 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव उठाने की अनुमति मांगी है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की ओर से 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक जयपुर में बुलाई गई थी। इस बैठक में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की आशंका के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के विधायकों ने विरोध करते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया था। साथ ही गहलोत खेमे के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर रात में जाकर इस्तीफा सौंप दिया था।

संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर राठौड़ ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री के घोषित सलाहकार को बधाई। उन्हें 91 विधायकों के इस्तीफों के कोर्ट में डेढ़ महीने से विचाराधीन मामले का अब ध्यान तो आया। विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 53 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, उन पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी

- **इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक देश शामिल होंगे जो भारतीय चुनाव आयोग की कार्यशैली को जानने में विशेष रूचि रखते हैं।**

नई दिल्ली, 22 जनवरी (वार्ता)। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग और मतदान की निष्पक्षता के विषय पर इस सप्ताह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है।

यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जबकि भारत में अपने मूल स्थान से देश में ही दूसरी जगह पढ़ाई-लिखाई, रोजी- रोजगार के लिए रह रहे मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहां से अपने क्षेत्रों में वोट देने की सुविधा किए जाने के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर विपक्ष ने आपत्तियां दर्ज की हैं।

विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन में गड़बड़ी की आशंकाएं भी जाहिर करता रहा है।

निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार यह सम्मेलन 23 और 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार करेंगे और समापन सत्र को निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे संबोधित करेंगे।

उपेन्द्र कुशवाहा ने जे.डी.यू. छोड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज किया

- **कुशवाहा ने कहा कि, मेरा भाजपा में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।**

नई दिल्ली, 22 जनवरी। बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से बड़ी ही हलचल मची हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी से नाराज चल रहे जे.डी.यू. संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जे.डी.यू. छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों पर अब खुद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "बीजेपी के नेताओं से मिलने का मतलब यह नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। ये सब निराधार अफवाहें हैं। मैं उनसे अस्पताल में मिला, इसका राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। मैं जे.डी.यू. में हूं,जे.डी.यू. कमजोर हो रही है लेकिन मैं इसे मजबूत करने के लिए काम करता रहूंगा।"

उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा में जाने की अटकलों पर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पार्टी में आते-जाते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे साफ-साफ लगा कि जे.डी.यू. और उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। कुशवाहा की जे.डी.यू. से दूरी का संकेत नीतीश कुमार के बयान से लगाया जा सकता है। नीतीश से जब कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कह कर चौंका दिया कि वो आते-जाते रहते हैं। अब आपको वो वजह बताते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के जे.डी.यू. छोड़ने का फैक्टर हो सकते हैं। कुशावाहा जेडीयू से नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़गी की 2 बड़ी वज़हें हैं। पहली वजह ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी आर.एस.एल.पी. का जे.डी.यू. में विलय किया तो उन्हें जे.डी.यू. संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संगठन में उनकी ज्यादा चलती नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि वो बिहार की महागठबंधन सरकार में डिप्टी सी.एम. या मंत्री पद चाहते थे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया।

विप्रो ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए आकलन शामिल है। यह व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया होती है। बयान में कहा गया है कि हमें 452 फ्रेशर्स को बाहर करना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण के बाद भी बार-बार असेसमेंट में खराब प्रदर्शन किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अनुसार, कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को सूचित किया कि वे प्रत्येक प्रशिक्षण लागत के लिए 75,000 रुपये का भुगतान करना था, लेकिन कंपनी ने खर्च को "माफ" कर दिया है। बताते चलें कि पिछले हफ्ते, कंपनी ने दिसंबर 2022 तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में उम्मीद से बेहतर 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चौथी तिमाही के लिए "मजबूत" बुकिंग के बारे में आशा व्यक्त की है।

अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन से 5 किलो हैरोइन बरामद हुई

सुरक्षाबलों ने सीमा पार से आये पाकिस्तानी ड्रोन को फायरिंग करके मार गिराया

नई दिल्ली, 22 जनवरी। अमृतसर में आज सुबह पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया। इलाके के कक्कड़ गांव में इस ड्रोन की तलाशी अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि ये ड्रोन सीमा पार से आया था, लेकिन तस्करों के पास हेरोइन की डिलीवरी से पहले ही पंजाब पुलिस की नजर में आ गया। इसे पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया। पंजाब पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि ये ड्रोन कहां से आया था और इसे किसने भेजा था। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बता दें कि पंजाब सीमा पर पाकिस्तान की हो रही लगातार ड्रोन घुसपैठ की वजह से एंटी-ट्रोन टीम की तैनाती की गई है। पिछले साल से अब तक कम से कम 25 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किये जा चुके हैं। इससे पहले भी जनवरी माह में ही सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) ने पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की साजिश को नाकाम किया था। पंजाब की भारत-पाकिस्तान अंतराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जवानों ने गोलीबारी कर खदेड़ दिया था।

'सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कई लोगों, खासकर युवाओं की मदद करेगा।

"प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "भारत में कई भाषाएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जीवंतता में इजाफा करती हैं। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे विषयों को मातृभाषा में पढने का विकल्प शामिल है।"

'न्यायपालिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संविधान के लिए विदेशी बताया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एन.जे.ए.सी.) और एक संबंधित संविधान संशोधन को रद करने के लिए शीर्ष अदालत पर सवाल उठाया है।

राष्ट्रपति जो बाइडन के घर पर एफ.बी.आई. ने फिर से छापा मारा

13 घंटे तक तलाशी चली, एफ.बी.आई. ने बाइडन के घर से कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किये हैं

- **इन दस्तावेजों का मिलना बाइडन के लिए ऐसे समय में राजनीतिक जवाबदेही बन गया है, जब वे फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं।**
- **इससे बाइडन की छवि को भारी नुकसान पहुँचने की पूरी-पूरी संभावना है।**

वॉशिंगटन, 22 जनवरी। अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी एफबीआई ने एक बार फिर राष्ट्रपति जो. बाइडन के विलमिंग्टन स्थित आवास की तलाशी ली है। इस दौरान गोपनीय दस्तावेज के तौर पर चिह्नित छः अतिरिक्त दस्तावेज बरामद किए हैं। विभाग ने बाइडन के कुछ हस्त लिखित नोट भी अपने कब्जे में लिए हैं। राष्ट्रपति के वकील बॉब बाउर ने यह जानकारी दी। बाइडन ने एफ.बी.आई. को अपने आवास की तलाशी लेने की स्वेच्छा से अनुमति दी, लेकिन तलाशी वारंट नहीं होने के बावजूद यह घटना असाधारण है।

बाइडन को 12 जनवरी को यह खुलासा होने के बाद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी कि बाइडन के वकीलों को मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले वाशिंगटन स्थित पेन बाइडन सेंटर में उनके एक पूर्व कार्यालय से गोपनीय रिकॉर्ड मिले हैं। इसके बाद वकीलों को बाइडन के विलमिंग्टन स्थित आवास के पुस्तकालय से उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के समय के छह और गोपनीय दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों का मिलना बाइडन के लिए ऐसे समय में राजनीतिक जवाबदेही बन गया है, जब वह फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। यह घटना पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उतार-चढ़ाव भरे कार्यकाल के बाद अपने कार्यकाल को अमेरिकी जनता के सामने बेहतर दिखाने की बाइडन की कोशिश को नुकसान पहुंचाती है। बाउर ने शनिवार को बताया कि एफ.बी.आई. ने शुक्रवार को जिन दस्तावेजों को कब्जे में लिया है, वे बाइडन के सीनेटर एवं उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल से संबंधित हैं, जबकि नोट उनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के हैं। उन्होंने कहा कि यह तलाशी करीब 13 घंटे तक चली।

बाउर ने बताया कि अभी न्याय विभाग ने रिकॉर्ड की समीक्षा नहीं की है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दस्तावेजों की गोपनीयता का क्या स्तर है और क्या एफ.बी.आई. द्वारा हटाए गए दस्तावेज गोपनीय बने हुए हैं या नहीं। आम तौर पर, गोपनीय दस्तावेजों को अधिकतम 25 वर्षों के बाद सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड को अपेक्षाकृत अधिक समय तक गोपनीय रखा जाता है। बाइडन ने 1973 से 2009 तक सीनेटर के तौर पर सेवाएं दी थीं। बाइडन ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा था, "हमने पाया कि बड़ी संख्या में दस्तावेज गलत जगह पर हैं, तो हमने उन्हें तत्काल न्याय मंत्रालय को सौंप दिया।"

जब बाइडन के आवास की तलाशी ली गई, तो उस समय प्रथम महिला जिल बाइडन वहां नहीं थीं। वह डेलावेयर के रेहोबोथ बीच स्थित अपने आवास पर सप्ताहांत बिताने गई थीं। अभी यह देखा जाना बाकी है कि क्या अन्य स्थानों पर संघीय अधिकारी और तलाशी लेंगे या नहीं।

बाइडन के निजी वकीलों ने पहले रेहोबोथ बीच आवास की तलाशी ली थी और कहा था कि उन्हें कोई आधिकारिक दस्तावेज या गोपनीय रिकॉर्ड नहीं मिला।

इस मामले ने ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद गोपनीय दस्तावेज और आधिकारिक रिकॉर्ड अपने पास रखे जाने संबंधी न्याय विभाग की जांच को जटिल बना दिया है।

न्याय विभाग का कहना है कि ट्रंप 2021 की शुरुआत में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद गोपनीय के तौर पर चिह्नित सैकड़ों रिकॉर्ड अपने साथ ले गए थे और उन्होंने सरकार के अनुरोध के बावजूद महीनों तक उन्हें नहीं लौटाया, जिसके बाद उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए एजेंसी को तलाशी वारंट के तहत कार्रवाई करनी पड़ी।

बाउर ने कहा कि एफ.बी.आई. ने व्हाइट हाउस से इस मामले में तलाशी पूरी होने तक टिप्पणी नहीं करने का अनुरोध किया है। तलाशी के दौरान बाइडन के निजी वकील एवं व्हाइट हाउस के वकील भी मौजूद थे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600